

आपका प्रश्न जो आपने मुझे याद दिलाया उस दिशा में भी सोच की आवश्यकता है और यह सोची जाएगी।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Next Question No. 442.

\*(The question (Shri Misa R. Ganeean was absent. For answer, vide col.... infra).

\*(The question (Dr. Sanjaya Sinh) was absent. For answer, vide col.... Infra).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 444. Shri Maheshwar Singh.

**भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विद्यालयों का चयन**

\*444. श्री महेश्वर सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेल-कूद संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से भारतीय खेल प्राधिकरण विभिन्न राज्यों में कुछ विद्यालयों का चयन करता है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस प्रयोजनार्थ चुने गये विद्यालयों को राज्य-वार संख्या कितनी है और ऐसी सुविधाएं

कितने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं ; और

(ग) उन्हें दिए जा रहे प्रशिक्षण का ब्योरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास (युवा कार्य और खेल विभाग) मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (कु. ममता बलरॉ) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अंतर्गत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 56 स्कूलों को अपनाया गया है। इस योजना में राज्यवार छात्रों का ब्योरा सलग विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिये)।

(ग) यह योजना 1985 में शुरू की गई थी, इसका लक्ष्य 8-12 वर्ष के आयु समूह में स्कूलों छात्रों में प्रतिभा की खोज करना था। इस योजना में एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, बास्केट बाल, फुटबाल, जिम्नास्टिक, हॉकी, तैराकी, टेबल टेनिस, वालीबाल तथा कुश्ती खेल-विधाएं शामिल हैं योजना में छोटी आयु में खेल उत्कृष्टता के साथ छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं की परिकल्पना है। इसका सम्पूर्ण खर्च भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा

विवरण

**अंगीकृत विद्यालयों में बच्चों की संख्या (राज्य-वार)-31.3.92 तक की स्थिति**

राज्य का नाम	विद्यालय का नाम	बच्चों की संख्या	
		लड़के	लड़कियां
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1. बैसली बाल उच्च विद्यालय तथा महाविद्यालय, सिकंदराबाद	17	—
	2. वी. पी. सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, विजयवाड़ा	25	14
	3. सेयोसा उच्च विद्यालय, बेनुकोण्डा	09	03

1	2	3	4
असम	4. सैनिक विद्यालय, गोलपाड़ा	12	—
	5. राजकीय बी. एच. एस. विद्यालय, गोलघाट	19	15
	6. डोन बोस्को स्कूल, गोहाटी	17	—
बिहार	7. सेंट इग्नेशियस हाई स्कूल, बिहार	38	—
	8. राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, राँची	—	44
चण्डीगढ़	9. शिवालयिक पब्लिक स्कूल, चण्डीगढ़	56	04
दिल्ली	10. एयर फोर्स बाल भारती स्कूल, नई दिल्ली	—	14
	11. ग्रामीण पब्लिक स्कूल, धौला कुमा, नई दिल्ली	29	—
	12. मर्से इण्टरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली	—	10
गोवा	13. सेंट एन्थनी हाई स्कूल, गोवा	09	—
गुजरात	14. चाखतर विद्या मण्डल, वल्लभ विधान नगर, गुजरात	12	13
हिमाचल प्रदेश	15. राजकीय उच्च विद्यालय, माजरा	—	—
हरियाणा	16. मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय, राई	23	22
	17. सी. आर. जेड सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, सोनीपत	44	—
जम्मू और कश्मीर	18. टिडले ब्रिस्को स्कूल, शेखबाग	06	—
	19. माल्विनसन बालिका विद्यालय, शेखबाग	—	01
कर्नाटक	20. सेंट जोसफ्स इण्डियन हाई स्कूल, बंगलूर	24	—
	21. माउण्टेन व्यू हाई स्कूल, चिकमंगलूर	10	14
	22. श्रीराम कृष्ण विद्याभाला, मैसूर	03	—
केरल	23. जी. बी. राजा खेल विद्यालय, केरल	12	20
मेघालय	24. सेंट एण्टनी हाई स्कूल, त्रिपुंग	27	—
महाराष्ट्र	25. प्रवारा पब्लिक स्कूल, प्रवारा नगर	31	01
	26. भौसला मिलिटरी स्कूल रामभूमि, नासिक	17	—
	27. संजीवन विद्यालय, पंचगुणी जिला सतारा	14	16
	28. मुक्तांगन इंग्लिश स्कूल, पुणे	18	11

1	2	3	4
मणीपुर	29. सैनिक स्कूल, इम्फाल	21	21
मध्यप्रदेश	30. राजकीय बहुउद्देशीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इन्दौर	13	—
	31. महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय बहु-उद्देशीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर	—	12
	32. जवाहरलाल नेहरू स्कूल, "भैल", भोपाल	07	—
मिजोरम	33. राजकीय उच्च विद्यालय, मैकडोनाल्ड हिल, मिजोरम	—	—
नागालैण्ड	34. जॉन राजकीय उच्च विद्यालय, विश्वेमा	22	—
उड़ीसा	35. सेंट मैरी गर्ल्स हाई स्कूल, पुन्दरगढ़	—	06
	36. डी.ए.बी. पब्लिक स्कूल, भुवनेश्वर	—	08
	37. बी.एस. उच्च विद्यालय, मुन्दरगढ़	38	—
पंजाब	38. राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, टाण्डा उर्मर, होशियारपुर	09	—
	39. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, जलंधर	—	12
	40. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, अमृतसर	—	—
राजस्थान	41. वनस्थली विद्यापीठ विद्यालय, वनस्थली	—	11
	42. भूपाल नोबलस माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर (राज.)	15	—
	43. श्री गुरुनानक खालसा उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्रीभंगानगर	16	—
सिक्किम	44. ताशी नामग्याल अकादमी, गंगटोक	19	08
तमिलनाडु	45. मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज उच्च माध्यमिक विद्यालय, चेटपुत	11	—
	46. श्री शारदा बालिका विद्यालय, सेलम	—	21
	47. सेंट जोसेफ माध्यमिक विद्यालय, कुड्डलोर	11	—
त्रिपुरा	48. उमाकान्त अकादमी अग्रतला, त्रिपुरा	10	—
उत्तर प्रदेश	49. उदयप्रताप इण्टर महाविद्यालय, वाराणसी	37	—

1	2	3	4
	50. कोलविन तालुकदार महाविद्यालय, लखनऊ	39	—
	51. एम.के.पी. इण्डिया महाविद्यालय, देहरादून	—	27
प० बंगाल	52. राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, कुशा नगर, प० बंगाल	—	27
	53. विद्यान नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय, साठलेक सिटी	40	—
	54. विक्टोरिया बाल विद्यालय करसिआंग दाजिलिंग	13	—
	55. डोव हिन स्कूल, करसिआंग	—	15
	56. तालडी मोहनचन्द उच्च विद्यालय, तालडी, प० बंगाल	36	20
		829	371
महायोग :			1200

श्री महेश्वर सिंह : उपसभापति महोदया, जहाँ तक मेरी जानकारी है 16 मार्च 1984 को स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया का एपेक्स बाडी के रूप में पंजीकरण किया गया था और इस उद्देश्य से किया गया था कि इस प्रकार के जो छात्र देश भर में हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए और खेल-कूद में भी प्रोत्साहन दिया जाए। 1987 तक इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रांतों में 66 स्कूलों का चयन किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि शुरू में ही ऐसे स्कूलों में भारत सरकार 5 लाख रुपया अनुदान के रूप में देगी। तत्पश्चात् हर वर्ष 50 हजार रुपया इन्फ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए और निर्माण के लिए देगी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों का, जो उनकी पढ़ाई पर, किताबों पर और उनके भोजन पर तथा आवास पर खर्च होगा वह भी भारत सरकार वहन करेगी। खेद का विषय है कि इस योजना में उतनी सफलता नहीं मिल सकी है जितनी कि मिलनी चाहिए थी। जैसाकि मैंने कहा कि 1987 में बच्चों की संख्या 1991 दिसंबर तक 1217 थी और स्कूलों की संख्या 66 थी, अब यह घट कर 56 रह गई है और

बच्चों की संख्या भी घट कर 1200 रह गई है। मैं जानना चाहूंगा कि इसके क्या कारण हैं और क्या भारत सरकार ने प्रदेश स्तर पर किसी समिति का कोई गठन किया है जो कि इस कार्यक्रम की समय-समय पर इस योजना की मॉनिटरिंग करती हो या जिला स्तर या तालुका स्तर पर या रिजलल स्तर पर कोई इस प्रकार की प्रतियोगिता करवाती हो, जहाँ ऐसे मेधावी छात्रों का चयन किया जाता हो?

कु. समता बन्जर्जी : मैडम, मैं माननीय सदस्य की आभारी हूँ जिन्होंने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि यह बात सच है, 1984 साल में नहीं लेकिन 1985 में एक स्कीम लांच किया था, यह एन.एस.एस. स्कीम है।

पहले इसका थोड़ा क्राइटेरिया है, जो स्कूल में बोर्डिंग फेसिलिटी मिलती है स्टूडेंट्स को, उसी स्कूल में उसको शिक्षा के लिए, खाने के लिए, खेल-कूद के लिए पूरा इंतजाम स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया करता है, लेकिन बहुत सारे स्कूल हैं जो ऐसा नहीं कर पाए हैं, इसीलिए स्पोर्ट्स अथारिटी आफ इंडिया की एक

एम्पायर कमेटी है जो टाइम टू टाइम रिव्यू करती है और रिव्यू करके अगर ऐसा कोई स्कूल निकलता है जिसमें बोडिंग फेसिलिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी आफ इंडिया इसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ टेक-अप करती है और स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि आप कोई अलग से स्कूल बताएं जिसमें होस्टल फेसिलिटीज हैं। होस्टल फेसिलिटी नहीं रहने से एक स्टूडेंट को हम लोग उधर में रखकर खेल-कूद में ट्रेनिंग नहीं दे सकते हैं। उसको शिक्षा, उसको खेल-कूद का ट्रेनिंग और उसको स्टडी पूरी दे सकता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी आफ इंडिया। इसी के लिए दो-चार स्कूल जो हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में एक स्कूल है—माजरा स्कूल, जिस स्कूल में पांच लाख रुपये हमने सौंकाशन किए थे और 2.5 लाख हमने रिलीज भी किए हैं, लेकिन उस स्कूल में अभी तक कोई बोडिंग फेसिलिटी नहीं है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को हमने रिक्वेस्ट की है कि आप कोई अल्टरनेटिव स्कूल दें जिसमें बोडिंग फेसिलिटी हो तो हम लोग कर सकते हैं।

**उपसभापति :** सैकिड सप्लीमेंटरी ।

**श्री महेश्वर सिंह :** उपसभापति महोदया, मैंने यह जानना चाहा था कि क्या कोई मानिटरिंग समिति बनाई गई है जो कि समय-समय पर जिला-स्तर पर तालुका स्तर पर या रीजनल स्तर पर बच्चों की प्रतियोगिता करवाती हो?

दूसरी मेरी सप्लीमेंटरी यह है कि जैसे कि आपने स्वयं कहा कि हिमाचल प्रदेश के माजरा स्कूल में एक भी बच्चा नहीं है। तो जो इस प्रकार के स्कूल हैं, उनके स्थान पर, उनको सूची से निकालकर दूसरे स्कूलों का अपन कर लिया गया है या प्रांतीय सरकारों को यह लिखा गया है कि इसके स्थान पर वह किसी दूसरे में स्कूल का नाम आपके पास प्रपोज करके भेजें? ये यह भी जानना चाहूंगा कि जब से यह योजना चली है, आज तक कितने बच्चों को ट्रेनिंग दी गई और कुल कितना भारत सरकार का खर्चा हुआ है?

**कु० ममता बनर्जी :** मैडम, माजरा स्कूल की जो बात है, मैं पहले ही बोल चुकी हूं कि हम लोग 2.5 लाख

रुपए रिलीज किए थे, लेकिन उनको जो बोडिंग फेसिलिटी देना था, वह नहीं दिया इसलिए हमारी जो एम्पायर कमेटी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी आफ इंडिया की, यह टाइम टू टाइम रिव्यू करती है, मानिटरिंग करती है, इसी के लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ मैं हम लोगों ने टेक-अप किया है और स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि आप एक अलग से स्कूल दीजिए जिसमें बोडिंग फेसिलिटी हो so that we can start them here. और मैडम, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि हमने कितनों को ट्रेनिंग दिया है, 1200 स्टूडेंट्स को अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं एन०एस०टी०सी० स्कॉम में और आउट डोर स्कॉम हमने चालू किया है। एक एस०टी०डी०सी० सेंटर चालू किया है, 22 थापरेजनल है और हम लोगों ने एक "साई" सेंटर चालू किया है और उस "साई" सेंटर में भी हमारे 700 से अधिक स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं।

**श्री महेश्वर सिंह :** वह फिर जवाब नहीं आया। मैंने कहा था कि कोई प्रतियोगिता होती है जिला स्तर पर?

**कु० ममता बनर्जी :** प्रतियोगिता तो होती है, प्रतियोगिता के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट का हम लोग पहले ही बोल चुके हैं मानिटरिंग समिति है। जो क्राइटेरिया है स्कूल एडाप्ट करने का, मैडम एक क्वेश्चन है "साई" का स्कूल के बारे में, "साई" का एडाप्ट करने के बारे में। जो प्रतियोगिता होती है और सम्मर टाइम में, स्कूल में जब छुट्टी रहती है, सब "साई" सेंटर्स से एक कोच उधर रहता है और उसको एक्सटेंसिव एंड इन्टेंसिव ट्रेनिंग देता है, उसको एक्सपोजर देता है और उसको तो पूरा पड़ोस में ही उसको ट्रेनिंग देता है। प्रतियोगिता तो होती है।

**एक माननीय सदस्य :** यह समझ में नहीं आया।

**श्रीमती सत्या बहिन :** उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा जो विद्यालयों का

खेल-कूद के प्रोत्साहन के लिए चयन किया जाता है, उसकी प्रक्रिया क्या है? क्योंकि जो लिस्ट दी गई है और उसमें जो नाम दिए गए हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश से जो मैं मनावती हूँ कि सबसे बड़ा प्रदेश है देशभर में, उसमें से कुल 3 विद्यालय चुने गए हैं जबकि अन्य प्रदेशों से 9-9 विद्यालय चुने गए हैं। तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या प्रक्रिया है, यह माननीय मंत्री जो बता दें?

**कु० समता बनर्जी :** मैडम, मैंने रिप्लाय में पहले ही कहा है कि 56 स्कूलों को एडान्ट किया है "साई" ने एन०एस०टी०मी में स्कीम है। हर स्टेट में हम लोग चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो रिक्मेंडेशन देता है, फेसिलिटी प्रवेलेबल है, उसमें हम करना चाहते हैं। यही उनका फाइटेरिया है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्शन कमेटी भी हमारी है, वह सेलेक्शन कमेटी जो स्कूल विजिट करती है उसको साइडिफिक वे में ट्रेनिंग में हम लेते हैं और जो-जो फाइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग में चुना जाता है।

**श्रीमती सत्या वहिन :** कूल स्कूल नहीं चुना है?

**कु० समता बनर्जी :** नहीं, कूल स्कूल भी है।

**श्री अजीत जोगी :** महोदया, साई द्वारा जो शालाओं को गोद लेने की योजना है, उस योजना का सही परिणाम नहीं निकला, क्योंकि बसिलोना ओलम्पिक में भारत का जो योगदान रहा है, यह उसमें परिलक्षित होता है कि सात वर्षों में हम शालाओं को, स्कूलों को गोद में लेकर ऐसे खिलाड़ी तैयार नहीं कर सके जो हमारे लिए किसी भी तरह का पदक जीत सकें। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रालय इस पूरी योजना में कुछ वृत्तियादी मौलिक परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रहा है? मेरी दृष्टि में समें एक जो सबसे बड़ी कमी और वृत्तियादी खामी है, वह यह है कि हम ऐसे बच्चों को जिनमें प्रतिभा है वह किसी शाला विशेष में

प्रवेश ले, ऐसा मजबूर करते हैं। उसकी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, स्थितितन्त्र उसकी मजबूरियाँ ऐसी हो सकती हैं कि जिस शाला को आपने गोद में लिया है उसमें न पढ़ सके। तो क्या विशेषकर ऐसे कुश्ती के क्षेत्र में बहुत में ऐसे अखाड़े हैं, एक पहलवान-पप्पू यादव जो काफी अच्छा लड़ा मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मैं उसके लिए बहुत दिनों से संघर्ष कर रहा हूँ। वह एक ऐसे अखाड़े में रहकर प्रशिक्षण ले रहा है जहाँ उसको किसी तरह की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। उस अखाड़े में चार-पांच ऐसे प्रतिभावान बच्चे तैयार किए हैं और वह शाला चला रहे हैं। वह चाहते हैं कि जो सहायता आप इन स्कूल के बच्चों को दे रहे हैं, प्रतिभावान खिलाड़ी बच्चों को जहाँ वह पढ़ रहे हैं, वही सुविधा दी जाए, न कि इन गोद में ली गई शालाओं में दी जाए। क्या ऐसा कोई वृत्तियादी परिवर्तन आप अपनी इस योजना में करेंगे?

**एक सम्मानित सदस्य :** पार्लियामेंट में अखाड़ा अच्छा है बीसे।

**कु० समता बनर्जी :** एन०एस०टी० सी० स्कीम के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसी में 8 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों को कुछ लोग ट्रेनिंग देते हैं। 1986 में यह स्कीम शुरू हुई है। आज 1992 में इस स्कीम को 6 वर्ष हो गए हैं। जो बच्चे इस ट्रेनिंग के अन्तर्गत हैं, मैडम, आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें जो 1200 बच्चे हैं। नेशनल लेवल से 666 मैडल हमारे बच्चों ने जीता है और इंटरनेशनल कम्प्टीशन में 14 मेडल मिले हैं। लेकिन अब इसका... (अवधान)

**श्री अजीत जोगी :** बसिलोना में तो कुछ नहीं हुआ?

**कु० समता बनर्जी :** वह डिफ्रेट क्वेश्चन है... (अवधान)

**श्री अजीत जोगी :** केवल भारत के स्तर पर कुछ करके संतुष्ट नहीं होना चाहिए।

**कु० ममता बनर्जी :** मैं आपके क्वेश्चन का पूरा रिप्लाई दूंगी। मैडम, यह हमने आठ वर्ष से शुरू किया है। 1986 में आठ वर्ष की उम्र में जिसको भर्ती किया गया था उसकी अब एज 14 वर्ष है। उनका इससे जो अचीवमेंट हुआ है, उनको 666 मेडल नेशनल लेबिल पर मिले हैं और 14 मेडल इंटरनेशनल लेबिल पर मिले हैं। बसिलोना जाने के लिए यह बच्चे अभी ट्रेड नहीं हैं। बसिलोना में जो चीज हुई है, मैडम, उस पर कॉलिंग अट्रेंशन भी राज्य सभा में एक्सेप्ट हुआ है। 11 तारीख में हम लोग उस पर जरूर डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैडम, अभी हम लोग जूनियर्स को ज्यादा एक्सपोजर देना चाहते हैं। जूनियर्स को एक्सपोजर देने के लिए हमने "कैच दैम यंग प्रोग्राम" स्टार्ट किया है। अब सीनियर्स को एक्सपोजर देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम जूनियर्स को ठीक से देगा तो वह ठीक हो जाएंगे। इसीलिए हमने ग्रास रूट से शुरू किया है और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ... (व्यवधान) खेल-कूद के लिए तो आपको जूनियर्स को एक्सपोजर तो देना ही है।

**श्री प्रमोद महाजन :** जूनियर्स को एक्सपोजर दे रहे हैं और सीनियर्स पागल हैं। ... (व्यवधान) मैं कह रहा हूं मिनिस्ट्री भी वही कर रही है ... (व्यवधान)

**कु० ममता बनर्जी :** मैडम, जूनियर्स को हम लोग एक्सपोजर दे रहे हैं और मैडम, आपको जानकर खुशी होगी कि हम लोग पंचायत लेबिल से नेशनल लेबिल तक एक पंचायत लेबिल टीम भी चालू कर रहे हैं। पंचायत लेबिल टीम ब्लौक-टू-ब्लौक चले और डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर आए और डिस्ट्रिक्ट लेबिल से स्टेट लेबिल पर आए और नेशनल लेबिल पर आए। तो हम लोग ग्रास रूट में जो राईट टू प्ले—खेल-कूद का अधिकार, सबको देने के लिए हम कर रहे हैं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have 30 questions on this, and we also have a calling attention motion.

PROF. SAURIN BHATTACHAR-YA: Madam Deputy Cha-man, this question has come on the heels of our dismal performance in the near-complete Barcelona Olympics. I think there is nothing very unusual in what happened in Barcelona with our team because that had been our performance in all the preceding Olympics, these successive Olympics, I think. The point is that we are far behind the international standard's in games and sports and steps have to be taken to overcome these short-comings. The question relates to an area on which depends the future of the country. That is, training to the school children, the young boys, by the Sports Authority of India. I would like to make a request to the Minister whose enthusiasm in whatever comes her way is well known. (Interruption). Perhaps, the CPM will also concur with me. You need not worry about it. The question is, does he consider the programme for training of school children adequate? That is, training 1200 students all over India. They might have won 361 medals. But in a country of 890 million people, is training 1200 students an adequate programme? The second point is, -----

THE DEPUTY CHAIRMAN: If you are brief, some other people can be accommodated.

PROF. SAURIN BHATTACHAR-YA: My second question is, why is the boarding house criterion insisted upon? Thirdly, is the overall grant to sports and games, that is Rs. 40 crores, enough to cover the entire ground or is it an apology?

KUM. MAMTA BANERJEE: Madam, I am grateful to the senior Member of this House. Though sports is a State subject, it is a fact that our funds are very limited and we are spending only Rs. 40 crores on this. And, this time, it is reduced to Rs. 12 crores. It is most unfortunate. In European countries, they are spending ten per cent of their Budget on sports. Even in Malaysia, they are spending

more than Rs. 1000 crores on sports. But our country is spending only Rs. 40 crores on sports. It is very difficult to create infrastructure. That is why we have involved the public sector and the private sector also to come forward and give some resource to sports so that we can build up our sports units. Madam, I request, through you, the hon. Members of this House to fight over this matter with the Planning Commission and the Finance Ministry. (*Interruptions*)

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: .. The Minister is right. We must recognise our dismal performance in Olympics. We must recognise the fact. (*Interruptions*).

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order please. Order. Order in the House please. (*Interruptions*).

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: .. You should take up the challenge.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Do not be that enthusiastic in this House Question No. 445.

#### **Popularisation of lab to land programmes**

\*445. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) in what manner 104 collaborating centres under the supervision of Eight Zonal Committees take the technology packages from the scientists to the farmers; and

(b) what effective and viable steps are taken to popularise lab-to-land programmes so that farmers could step up their production?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI K. C. LENKA): (a) The technology packages are transferred by the scientists under the Lab to Land Programme at 104 Lab to land centres located in ICAR Institutes, State Agricultural Universities, Krishi Vigyan Kendras and selected Voluntary

Organizations, through demonstrations, training and farm advisory services to small and marginal farmers and landless agricultural labourers. Eight zonal coordinating units of the Council supervise and monitor the Lab to Land programme in their respective zones.

(b) Under the Lab to Land Programme, small and marginal farmers and landless agricultural labourers are adopted by the lab to land centres. The survey is conducted to find out the resource endowment of the adopted farmers. The suitable low cost technologies are identified and demonstrated to the farmers for stepping up their production.

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Madam, agricultural production is to be increased and productivity is to be improved. For that, the Lab to Land Programme is very much essential. Not only that. The Lab to Land Programme should be effective. I want to know whether there are enough infrastructural schemes to disseminate all the findings to the agriculturists. In this connection, I will be very glad if the Minister there shed some light on the object of the project. At the same time, I also want to know from him as to how many centres are there in Tamil Nadu to disseminate such information.

SHRI K. C. LENKA: Madam, the Lab to Land centre deals with the poor farmers in the villages and demonstrates to them the low cost technologies. The main purpose of this Programme is to bring the farmers and the scientists in close contact and to introduce the relevant low cost technologies which would help in diversification of labour use and creating supplementary sources of income in the fields of agriculture, animal husbandry, sericulture, apiculture, and fisheries. Madam, these lab to land centres give vocational training to marginal and small farmers and landless labourers so that they can have additional income. So far as Tamil Nadu is concerned, in Tamil